Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

भारत-रूस संबंध में चीन : एक विवेचन

डॉ. सरिता सिंह
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उ.प्र.
ईमेल: drsaritasingh1020@gmail.com

शोध सारांश

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इसकी ऐतिहासिक परंपरा की जड़े हजारों वर्ष पुरानी है। निकटवर्ती संलग्न पड़ोसी राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही अपनी अलग पहचान बनाए रखने का प्रयत्न कर सकते हैं। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका संप्रभु राष्ट्र है और इनके अपने अलग राष्ट्रीय हित स्पष्ट है, परंतु इनमें से कोई भी देश भारतीय विदेश नीति के उतार-चढ़ाव की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी कारण कोई भी महाशक्ति चाहे अमेरिका हो या सोवियत संघ राजनयिक दृष्टि से भारत की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। भारत की भू-राजनैतिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि उसका अंतरराष्ट्रीय राजनयिक महत्व बढ़ जाता है।

मुख्य शब्द**:** भारत, चीन, सोवियत संघ, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, अस्त्रीकरण, अर्थव्यवस्था, सामरिक सम्बन्ध।

प्रस्तावना

भारतीय विदेश नीति के संबंध में सोवियत संघ (वर्तमान रूस) का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद के वर्षों में थोड़े असमंजस व तनाव के दौर से गुजरने के बाद इनमें तेजी से सुधार हुआ और एक बार यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद इनमें तेजी से प्रगति हुई। सोवियत संघ ने बड़े पैमाने पर तकनीकी सहायता दी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के असरदार राजनयिक समर्थन भी दिया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय सोवियत संघ के साथ भारत की मैत्री संधि सामरिक महत्व की सिद्ध हुई तब से प्रत्येक दो दशक के बाद इस संधि का पुनर्नवीकरण हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण भूमि, रूस के साथ इसके संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहेंगे।

1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत चिंतित हुआ हालांकि रूस ने स्पष्ट किया कि भारत से उसके संबंध पूर्ववत बने रहेंगे। भारत और रूस दोनों देश एक दूसरे से अपने संबंध को मधुर बनाने के उद्देश्य से समय≤ पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री एवं राष्ट्रपति ने एक दूसरे के देशों की यात्रा कर संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना कोई किसी का स्थाई मित्र होता है और ना स्थाई शत्रु। विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर विदेश नीति का संचालन करते हैं।

भारत-रूस सम्बन्ध

भारत-रूस संबंधों में कई सामरिक कारणों से चीन एक महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा। पहला, रूस और चीन के बीच सामरिक साझेदारी का बढ़ना है। रूस और चीन के बीच वैचारिक निकटता तो है ही दोनों देशों की सुरक्षा चिंताओं व हितों में भी सामरिक रूप से साम्; है दोनों देश एक दूसरे के साथ सामरिक साझेदारी वह सहयोग स्थापित कर चुके हैं।

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

भारत-चीन सम्बन्ध

दूसरा, चीन की महत्वाकांक्षा है कि भविष्य में वह विश्व शक्ति के रूप में उभरे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु चीन ने चार क्षेत्रों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू कर रखे हैं। रक्षा के क्षेत्र में चीन अपना आधुनिकीकरण पूरा करने के लिए रूस के शस्त्रो पर निर्भर है। दूसरी ओर रूस चीन को अपनी शस्त्र प्रणाली बेचकर चीन से चीनी मुद्रा प्राप्त करना चाहता है रूस के लिए चीन की सशक्त मुद्रा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए चीन नहीं चाहता कि रूस द्वारा भारत को अत्यधिक सैन्य सहायता दी जाए क्योंकि ऐसी कोई भी सहायता चीन व पाकिस्तान दोनों के हितों के विरुद्ध है।

चीन-रूस सम्बन्ध

जब तक चीन पाकिस्तान, से अपने संबंधों को नहीं तोड़ता या इसमें कमी नहीं लाता तब तक भारत -रूस- चीन की किसी त्रिपक्षीय धुररी या सामरिक साझेदारी की स्थापना एक काल्पनिकता जैसी है। ऐसी किसी साझेदारी की स्थापना में कई समस्याएं हैं। प्रथम, चीन, भारत और जापान को एशिया में अपनी प्रभुता को चुनौती दे सकने वाली प्रतिद्वंदी शक्ति के रूप में देखता है। इसके लिए उसे (चीन) पाकिस्तान जैसे सहयोगी चाहिए जो इस क्षेत्र में चीन के सामरिक दावो एवं हितों को पूरा करने में मदद दे। दूसरा, चीन के पास पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1963 में पाक- चीन समझौते के अंतर्गत चीन को सौंप दिया गया था। यह अधिकृत भूभाग भारत के खिलाफ किसी भी कार्यवाही में चीन व पाकिस्तान दोनों के लिए सामरिक महत्व रखता है इसी क्रम में कारगिल संघर्ष के बाद भारत द्वारा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी का लेह में निर्माण किया गया है । चीन व पाकिस्तान के लिए भारत के इन कदमों को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। इन सब जटिलताओं के चलते चीन द्वारा भारत या रूस से बिना किसी लाभ के की जाने वाली सामरिक साझेदारी के लिए पाकिस्तान को कम महत्व देना संभव नहीं है। हालांकि चीन यहां जरूर चाहता है कि बहुधुरवी; विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए रूसी - चीन प्रयासों को भारत समर्थन दें। चीन द्वारा रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को शांति और स्थायित्व लाने वाली यात्रा बताया गया।

भारत-चीन-रूस सम्बन्ध

चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी चीन के समाचार पत्रों के द्वारा भारत- रूस -चीन के बीच संबंध बढ़ाने संबंधी वक्तव्य को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया । वक्तव्य में पुतिन ने एशियाई देशों के साझा हितों को खुले पन व पारदर्शिता से सुलझाने में रूस -चीन और भारत द्वारा सहयोग किए जाने की आवश्यकता बताई। द चाइना टेली समाचार पत्र ने लिखा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी नई रूपरेखा या नई व्यवस्था की स्थापना रूस, चीन तथा भारत की भागीदारी के बिना संभव नहीं है भारत की चिंता का विषय अभी भी चीन द्वारा पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल विकास कार्यक्रम को दिया जा रहा सहयोग है। भारत का दृष्टिकोण है कि ‘‘चीन एक परमाणु खेल खेल रहा है जिसमें वह पाकिस्तान का तो सहयोग करता है परंतु बात शांति की करता है’’। इसलिए कई भारतीय विदेश नीति के विश्लेषक चीन के प्रति कठोर नीतियां अपनाने की बात करते हैं।

The Asian Thinker

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से भारत रूस व्यापार संबंधों में भी नई संभावनाएं बढ़ी हैं। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के समय इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत-अमेरिका संबंधों में बढ़ती निकटता को देखते हुए रूस ने भी पुराने प्रेमी की तरह भारत से पुनः संबंध बढ़ाने का निश्चय लिया। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र नें लिखा कि दोनों देशों को शीत युद्ध के बाद मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप नए सिरे से अपने संबंध को बढ़ाना होगा।

रूस चीन संबंधों में हालिया विकास

अमेरिका की एक ध्रुवीयता को खारिज करने में एक साथ होने के बावजूद रूस और चीन के बीच संबंध जटिल बने हुए हैं। यद्यपि की युद्ध के अधिकांश दशकों में और पूर्व सोवियत संघ के बीच संबंध उदासीन थे जिसका कारण अविश्वास व सैद्धांतिक मतभेद था। संबंधों में सुधार लाने का श्रेय मिखाईल गोर्बाचोव को जाता है जिन्होंने चीन का दौरा कर संबंध बेहतर करने का प्रयास किया। रूस और चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के आधार के रूप में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, गैर- आक्रामकता एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर- हस्तक्षेप, समानता व पारस्परिक लाभ एवं शांतिपूर्ण सह- अस्तित्व के लिए पारस्परिक सम्मान की घोषणा की। वर्ष 2001 में दोनों देशों ने अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए जिससे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ।

रूस ने वर्ष 2014 के क्रीमिया अधिग्रहण के कारण रूस के अमेरिका ,नाटो और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों में तीव्र गिरावट आई उसने चीन के साथ संबंधों की संभावनाओं और सीमाओं को प्रकट किया। जब अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस ने चीन की ओर रुख किया रूस ने चीन के निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और वर्ष 2025 से 30 वर्षों के लिए चीन को प्रतिवर्ष 30 बिलियन क्यूबिक मीटर पूर्ति करने हेतु रूसी राज्य एकाधिकार गैस निर्यातक गजप्रोम के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया। जून 2021 में दोनों देशों ने एक आभासी बैठक में संधि का विस्तार किया जहां रूस ने दावा किया कि ‘‘रूसी -चीन संबंध वैश्विक मामलों में एक स्थिर भूमिका निभाता है‘‘। जनवरी 2022 में दोनों देशों ने एक पाइप लाइन पावर ऑफ साइबेरियन -2 के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो 30 वर्षों हेतु वार्षिक आपूर्ति में दस् इ.ब.उ. गैस को जोड़ेगा। चीन और रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ संबंधों के साथ यूक्रेन संकट और रूस दोनों को एकजुटता व्यक्त करने का अवसर प्रदान कर रहा है। यूक्रेन संकट का दोषी रूस को मानकर जहां एक तरफ पश्चिमी देश रूस पर वित्तीय और बैंकिंग प्रतिबंध लगाते हैं तो चीन से रूस की सहायता करने की अपेक्षा की जा सकती है जो कि संभवत वैकल्पिक भुगतान विधियों के रूप में हो सकती है।

भारत के लिए उपर्युक्त नीतियां

भारत के लिए सबसे बेहतर विकल्प यह है कि वह रूस -चीन संबंध और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखें और यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत को अपने स्वयं के स्थान को खोने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। रूस के साथ भारत के संबंध पहले जैसे नहीं रहे हैं लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे दोनों पक्ष पारस्परिक लाभप्रद स्थिति के रूप में देखते हैं जैसे रूस- चीन के बयान में भारत के साथ चीन का सीमा विवाद का उल्लेख

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

नहीं था दूसरा रूस से जुड़ी रेडफिश नामक एक मीडिया कंपनी द्वारा कश्मीर एवं फिलीस्तीन के बीच समानता से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी जिसके बाद रूसी दूतावास ने स्पष्ट किया कि रेडफिश मीडिया एक आधिकारिक मीडिया नहीं है और यह दोहराया कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त यदि अमेरिका और रूस के बीच मामलों में सुधार होता है तो क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण में शक्ति गतिशीलता के कारण उत्पन्न संरचनात्मक बाधाओं को कम किया जा सकता है।

दोनों देशों के बीच कम संघर्षपूर्ण संबंध भारत को राहत प्रदान करेगा साथ ही अमेरिका और चीन के चल रहे संघर्ष और चीन के साथ रूस के गहरे संबंध भारत के लिए चिंता का विषय है इन परिस्थितियों में भारत को रूस चीन और भारत के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जो भारत और चीन के बीच अविश्वास व संदेह को कम करेगा।इसके अलावा भारत को कूटनीतिक तरीके से अमेरिका के साथ भी संबंध को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। चीन चूकि विश्व शक्ति बनने का सपना देखता है इसीलिए भारत को चीन के साथ बेहद चालाकी पूर्ण तरीके से संबंध रखने चाहिए क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है की भारत सदैव चीन के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया लेकिन चीन ने हर बार भारत के साथ छल किया इसका जीता जागता उदाहरण 1954 का पंचशील सिद्धांत और 1962 में चीन के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण से स्पष्ट है हालाँकि 1962 के भारत और वर्तमान भारत की स्थिति में काफी अंतर है लेकिन फिर भी भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी भू-राजनैतिक स्थिति और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर रूस, चीन अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने के साथ-साथ पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध निरंतर मधुर रखने का प्रयास करना चाहिए।

भूतपूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे.कलाम ने 13 मई 1998 को हुए परमाणु परीक्षण पर अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि ''नाभिकीय अस्त्रीकरण अब पूरा हो गया है। हमारे पास नाभिकीय अस्त्रीकरण के लिए भरोसेमंद आकार, वजन, निष्पादन क्षमता और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ है।'' इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षणों ने कप्यूटर अनुकरण में भारत की क्षमता को अत्यधिक बढा दिया है और अब हम इस अवस्था में पहुॅच गए हैं कि यदि आवश्यक समझा गया तो हम भविष्य में इससे आगामी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि भारत ने सन् 1974 में प्रथम विस्फोट कर परमाणु शक्ति का सम्पन्न होने का दावा विश्व समुदाय के समक्ष पूर्व ही रख दिया था। भारत के उभरती हुयी इस ताकत से पूरा विश्व समुदाय आश्चर्यचकित रह गया। विशेषतौर पर महाशक्ति देशों जैसें, अमेरिका, रूस चीन, फ्रांस, ब्रिटेन एवं जापान ने इसकी तीखी आलोचना की एवं भारत पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी, लेकिन भारत इन प्रतिबंधों को झेलते हुए अपने परमाणु कार्यक्रमों को सुदृढ बनाए रखने में कोई कसर नही छोडी। इसलिए भारत महाशक्ति देश के परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाने हेतु सी.टी.बी.टी. नामक निःशस्त्रीकरण की योजना बनायी। इस निःशस्त्रीकरण समझौते के अनुसार हस्ताक्षर करने वाले देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकेंगे भारत ने अब तक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत को विश्वास है कि अमेरिका परमाणु कार्यक्रमों के विकास के सन्दर्भ में मदद करेगा तथा भारत को पूरे एशिया महाद्वीप में शाक्तिशाली बनाने का पूरा प्रयास करेगा एवं एक दिन भारत इजराइल के समकक्ष परमाणु शक्ति सम्पन्न देश बन जाएगा।

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

दिसंबर 1954 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में नाभिकीय परीक्षणों पर पूर्ण रोक लगाने के प्रस्ताव को दोहराया, परंतु मतदान नहीं कराया गया। सन् 1958 में जब अमेरिका ने परीक्षण के अस्थायी निलंबन आदेश पर बरबरी के सोवियत संघ प्रस्ताव को रद्द कर दिया, तब दोनों ने विशेषज्ञों की समिति गाठित की। इसके बाद आंशिक परीक्षण प्रंतिबंध संधि ;सी.टी.बी.टी.द्ध का निर्णय लिया गया, जिसने वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और समुद्र में नाभिकीय परीक्षणों पर रोक लगा दी। अनेकानेक गैर नाभिकीय हथियार वाले देशों के कहने के वावजूद भी सन् 1977 तक किसी वादानुवाद के आधार नजर नहीं आ रहे थे । इसके पूर्व दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जिसके वजह से इस वार्ता में कोई पहल नहीं दिखाई दे रहा था।

आखिरकार दोबारा महाशक्ति देशों-सोवियत संघ, बिटेन अमेरिका ने सी.टी.बी.टी. पर वार्ता प्रारंभ की जो सन् 1977 से 1980 तक चली निरीक्षण की प्रकिया और ढंग, अवधि, प्रयोगशाला परीक्षण आदि ऐसे मुद्दों में से थे। जिनका हल नहीं निकल पाया। सन् 1982 में रीगन प्रशासन ने सी.टी.बी.टी. के लिए प्रयास करने की अपनी नीति समाप्त कर दी। 20 जुलाई, 1982 को अमेरिका ने त्रिपक्षीय बातचीत को भी औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। प्रतिबंध एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया ।

जब रूस ने 1992 में एन.पी.टी. पर हस्ताक्षर कर दिया तो रूस के पास अमेरिका से कहीं ज्यादा नाभिकीय अस्त्र थे। चीन ने 5 मई 1993 को 80-160 के.टी. की ऊर्जावाला एक विस्फोट किया। फ्रांस ने अप्रैल 1992 से दिसंम्बर 1992 नाभिकीय परीक्षण पर रोक लगाने की। पिछले तीन वर्षा में फ्रांस ने प्रतिवर्ष अमेरिका को छोडकर, अन्य देशो के मुकाबले काफी अधिक परीक्षण किए थे।

चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे ऐसा लगाता है। कि वह सी.टी.बी.टी. बातचीत करने के लिए गंभीरता से तैयार है। इसने सन् 1992 में दो परीक्षण किए जितने कि पिछले तीन साल में कुल कि किए थे। 21मई, 1992 को चीन ने इतिहास में बड़ा भूमितग परीक्षण किया।

अमेरिका ने इस त्रिपक्षीय वार्ता को बीच में तोड़ दिया। इसके उपरांत सन् 1982 से 1983 में बातचीत करने वाली सभा ने परीक्षण प्रतिबंध पर एक तदर्थ सहायता सभा की स्थापना की जो कि वास्तविक रूप में संधि पर बातचीत नहीं कर सकता है। आधिकार के संबंध में असहमति होने के कारण यह कोई ठोस प्रगति नही कर पाई । इसी कारण सन् 1984 के बाद अगले कई वर्षों तक सी.डी. तदर्थ समिति की स्थापना नही कर सकती, यद्यपि उसके पास विभिन्न वर्गों में संबंध में लिखित अधिकार पत्र था। सन् 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, सी.टी.टी.बी. और पी.इन.ई. संधियों के मूल लेखों को संशोधित करने और अंततः चरणबद्ध तरीके से परीक्षण प्रतिबंध तक पहुंचने के लिए सहमत हो गए।

उपसंहार

सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् रूस का उदय हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने सन् 1991 में नाभिकीय परीक्षणों पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी। 1992 में राष्ट्रपति येल्तसिन ने इस एन.पी.टी. समीक्षा और विस्तार सम्मेलन से प्रेरित होकर 1994 में सी.टी.बी.टी. पर पुनः बातचीत प्रारभ हुई। यूरोप और अमेरिका की अधिकांश गैर नाभिकीय अस्त्रों वाले देश आलोचना करते हैं। इसलिए अमेरिका की नीती में प्रमुख

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

प्रत्यावर्तन हुआ। यद्यपि सी.टी.बी.टी. के लिए लगभग सभी तकनीकी और राजनीतिक मापदंड सर्वज्ञात थे, फिर भी पहला साल का कुछ समय इस मुद्दे को देखने में लगा। सन् 1994 नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध (एन.टी.बी.) समिति की रिपोर्ट, अठारह पृष्ठ में कार्यवाही सारांश के रूप में प्रकाशित हुई, जिसके बाद वर्गीय कोष्ठकों में वैकल्पिक प्रस्तावों और तकनीकों सहित पाठ का पंचानवे पृष्ठीय परिशिष्ट था।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:

1. परूथी, डा0 आर0के0, भण्डारी, डा0 दीपा: चीन का इतिहास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. शूईग, वाड.: चीन और भारत, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
3. खान, डा0 वसीम अहमद: भारत-चीन-पकिस्तान सम्बन्ध, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. गजराज, पदम सिंह, गजराज, चेतना: भारतीय राजनीति, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुददे और चुनौतियां, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
5. सियाराम, डा0: नई सदी में भारत, चुनौतियां एवं समाधान के उपाय, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. श्रीवास्तव, अजय मोहन, वर्मा, जगदीश प्रसाद, मिश्र अजय कुमार, पाठक कनक बिहारी: भारत के लिए खतरे-आन्तरिक से वैश्विक, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
7. 'भारत चीन एक सुर में बोलेगें' दैनिक भाष्कर, 22 मई 2013, नई दिल्ली।
8. 'घुषपैठ पर होगी बातचीत', राजस्थान पत्रिका, 19 मई, 2013, नई दिल्ली।
9. हिन्दुस्तान टाइम्स: समाचार पत्र नई दिल्ली।
10. इण्डिया टूडे: समाचाार पत्र उत्तर प्रदेश (नोएडा)।
11. द हिन्दू: समाचार पत्र नई दिल्ली।
12. दैनिक जागरण: समाचार पत्र गोरखपुर।

The Asian Thinker